



१३८१४७

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1987/ज्येष्ठ 4, 1909

No. 279]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1987/JYAISTHA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation*

वित्त भ्राता

(राजस्व विभाग)

(विभेन कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1987

प्रधिसूचना

आयकर

भा. का. नि. 526(अ) —भारत सरकार द्वारा चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य ने आय पर करों के सम्बन्ध में शीर्षे नियमानुसार के परिवार और राजस्व अपबंधन को शीर्षने के लिए एक करार घोषित किया है; जैसा कि इस अधिसूचना के उपायमध्य में विविहित है;

और यह उक्त करार के अनुच्छेद 28 की ओरानुसार भारत और चेकोस्लोवाकिया में दोनों देशों के विभिन्न विधानों द्वारा दोहरे करार ली गई है जो उक्त करार को शीर्षने के लिए आवश्यक है;

और यह करार के अनुच्छेद 28 की ओरानुसार उक्त दोनों देशों के विभिन्न विधानों के द्वारा इस आशय की टिप्पणी की आदान प्रवान हो गया है;

अतः यद्य, आजकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (नाम) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा

24(क) वारा प्रदत्त विभिन्नों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा नियंत्रण देती है कि उक्त करार के मध्ये उपन्यधि भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

उपायमध्य

भारत सरकार

और

चेकोस्लोवाकिया ममाजवादी गणराज्य की सरकार

के द्वारा

आय पर करों के संबंध में दोहरे कायदान के परिवार और राजस्व अपबंधन को शीर्षने के लिए करार

भारत सरकार और चेकोस्लोवाकिया ममाजवादी गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कायदान के परिवार और राजस्व अपबंधन को शीर्षने के लिए करार करने की इच्छा से,

निम्न नियम अनुसार सहमत दुई हैं।

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उम्म विभिन्नों पर लागू होगा जो किसी एक व्यक्ति के विविदाकारी शर्यों के नियासी हैं।

अनुच्छेद—२

करार के अन्तर्गत आगे बाले कर

(१) यह करार जिन करों पर आगे होगा ने है ---

(क) भारत के मामले में,

(१) आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रधीन लगाया गया आगकर विसमें आयकर पर कोई अधिकार भी आभिल है।

(२) कम्पनी (आभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के प्रधीन लगाया गया अतिकर,

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)।

(च) चेकोस्लोवाकिया के मामले में:

(१) लार्जों पर कर,

(२) मजदूरी कर,

(३) शाहिस्तिक लथा कलात्मक लार्जकलापों से आय पर कर,

(४) क्रिप्टकर,

(५) जनसंघ्या आय पर कर,

(६) गृह कर,

(जिसे इसके बाद "चेकोस्लोवाकिया कर" कहा गया)।

2. यह करार किसी भी भवित्व प्रथवा सारतः इसी प्रकार के उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-१ में उल्लिखित करों के अधिकार अथवा उनके स्थान पर दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा लगाये जाएंगे।

3. प्रस्तुत वर्ष के अन्त में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने दोनों में उन करों के संबंध में किए गए भलवत्पूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार के विषय हैं और मंगत अधिनियमों और विनियमों की प्रतियों भेजेंगे।

अनुच्छेद—३

भारतीय परिवायां

1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा श्रेष्ठता नहीं हो :

(क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्य शेव और उसमें प्रादेशिक समूह और उसके ऊपर का आकाशी क्षेत्र लथा कोई भी अन्य समूद्री क्षेत्र आभिल है, जिसमें भारतीय कानून के अनुसार नथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून/समूद्री कानून पर भयुक्त राष्ट्र अधिसमय के अनुसार भारत के भवेभौम अधिकार, अन्य अधिकार तथा थोकाधिकार हो;

(ख) "चेकोस्लोवाकिया" शब्द में अभिप्रेत है चेकोस्लोवाकिया समाज-वादी गणराज्य,

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" प्रीर "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से, संबंध की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा चेकोस्लोवाकिया अभिप्रेत है,

(घ) "कर" शब्द में, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा चेकोस्लोवाकियाई कर अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द का ग्रथ वही होगा जो अलग-प्रत्यग संविदाकारी राज्यों में लागू करायान कानूनों में इसके लिए दिया गया है,

(च) "कम्पनी" शब्द में कोई ऐसा निर्मामित निकाय अथवा कोई ऐसी मत्ता अभिप्रेत है, जो अलग-प्रत्यग संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत एक कंपनी के रूप में मानी जानी है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों में कभी: एक संविदाकारी राज्य के किसी

निवासी द्वारा सकालित उद्यम भी तूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा सकालित उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "अधम प्राधिकारी" शब्दों से अभिप्रेत है, जो उन हाँ मामल में क्षेत्रीय सरकार का विस मन्त्रालय (राजस्व विभाग), और चेकोस्लोवाकिया के मामले में चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य का विन मन्त्री अथवा उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा इस करार के उपर्योगों के प्रवर्तन में, किसी भी पथ का, जो यहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ को अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उम संविदाकारी राज्य में लागू उन पर कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस करार के विषय है।

अनुच्छेद—४

आर्थिक अधिकार

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पर से अभिप्रेत किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो उम संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार उम संविदाकारी राज्य का निवासी है।

2. जहाँ पैराग्राफ-१ के उपर्योगों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहाँ इस करार के प्रयोजनार्थ उमकी निवासीय प्राप्तियां निम्नलिखित नियमों के अनुसार तथ की जाएँगी:—

(क) वह उम संविदाकारी राज्य का निवासी भाना जाएगा जिसमें उसे कोई स्थायी गृह उपलब्ध हो। यदि उसे शीर्षी संविदाकारी राज्यों में स्थायी गृह उपलब्ध हों तो यह उम संविदाकारी राज्य का निवासी भाना जाएगा जिसके भाथ उमके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर होंगे (इसके बाद जिसे "उमके महान् पूर्ण हिस्सों का केन्द्र" कहा गया है),

(ख) यदि उम संविदाकारी राज्य का अवधारण नहीं किया जा सकता हो तो उमके महान् पूर्ण हिस्सों वा केन्द्र हो, अथवा यदि उसे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उम संविदाकारी राज्य का निवासी भाना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि यह दोनों ही राज्यों में आवतन रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में आवतन नहीं रहता हो तो वह उम राज्य का निवासी भाना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक महसूल द्वारा इस प्रमाण का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति गे भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ-१ के उपर्योगों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसे उम संविदाकारी राज्य का निवासी भाना जाएगा जिसमें उमका वास्तविक प्रबन्ध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद—५

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजन के लिए "स्थायी संस्थापन" पर से कारोबार का यह निरिचन स्थान अभिप्रेत है, जिसमें उथम का कारोबार समूलीय अथवा अणतः चलाया जाना है।

2. "स्थायी संस्थापन" पर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) प्रबन्ध का कोई स्थान;

(ख) कोई शास्त्रा,

- (ग) कोई कार्यालय,
- (घ) कोई कारोबार,
- (क) कोई कार्यशाला अथवा भावनाशाला,
- (च) कोई खान, खदान तेल-क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्मण का अन्य स्थान;
- (छ) भवनधूमधातु अथवा निर्माण अथवा संरचना परियोजना अथवा उससे पंडित्य पर्यंतीकी नियाकलाप जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा पर्यंतीकी क्रियाकलाप छ: महीने से अधिक अवधि तक जनना है अथवा जहाँ ऐसी परियोजना अथवा पर्यंतीकी क्रियाकलाप, मरीनरी अथवा उपस्कर के बिक्री में आनुपर्याप्त होने की हालत में, ऐसा अधिक नक जारी रहता है जो छ: महीने से अधिक नहीं है, और एसी परियोजना अथवा पर्यंतीकी क्रियाकलाप के लिए वेद्य प्रभार मरीनरी अथवा उपस्कर के बिक्री रूप के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

3. "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं है:

आएगा:

- (क) उद्यम के माल अथवा तिजारी माल के भण्डारण अथवा उसके प्रवर्णन के उद्देश्य के लिए ही सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम के माल अथवा तिजारी सामान का स्टाक केवल भण्डारण अथवा प्रवर्णन के प्रयोजनार्थ रखना;
- (ग) इसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा तिजारी माल का स्टाक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा तिजारी माल का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान रखना;
- (ङ) विजापित करने, सूचना देने के लिए अथवा वैकानिक अनुसंधान कार्यकलाप, जो उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में अनन्यतः प्रारंभिक अथवा सहायक रूप के हों, के अनन्यतः प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान रखना, लेकिन यदि वह उद्यम इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई अन्य नियत स्थान रखता है तो वह उपर्युक्त लागू नहीं होगा।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम अथवा उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करने वाले अवित्त को जो स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न हो और जिस पर पैराम्पराक 5 लागू होना हो—प्रयोक्तव्य संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापना माना जाएगा, यदि:

- (i) वह उस संविदाकारी राज्य में उस उद्यम अथवा उद्यम की ओर से बातचीत करने का तथा संविदाएं करने का प्राविकार रखता है और उसका प्रावितन प्रयोग करता है जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पर्यवर्ती रूप के क्रय तक ही सीमित न हो; अथवा
- (ii) वह प्रयोक्तव्य संविदाकारी राज्य में उद्यम के माल अथवा पर्यवर्ती रूप में ऐसा स्टाक रखता है, जिसमें से वह अवित्त उद्यम अथवा उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पर्यवर्ती रूप से किसी वित्ती देता है; अथवा
- (iii) वह प्रयोक्तव्य संविदाकारी राज्य में अनन्यतः अथवा संगमग्रन्थित अनन्यतः उद्यमों के लिए, अथवा उसमें नियतक रूप से याने उद्यमों के लिए अवित्त है जो उसके प्राप्त करता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम या दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वहाँकह संसद् स

राज्य में किसी उद्यम, सामाजिक अवित्त एजेंट अथवा वस्तुतः स्वतंत्र हैसियत वाले किसी प्रथ्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करते हैं, जहाँ ऐसे व्यक्ति प्रयोक्तव्य कारोबार का काम सामाजिक रूप से कर रहे हों।

6. कोई ऐसी कंपनी जो संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में (जहाँ किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा प्रथ्य) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है तो केवल इष्ट तथ्य से उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी एक कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

7. एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि वह दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कारोबार चलाता है जिसमें लोक मनोरंगनकर्ताओं (जैसे रामंच, भवित्व, रेतियों अथवा टेलिविजन कलाकारों और संगीतगीतों) अथवा विलासियों की सेवाएं प्रदान करता रामिल ही। जब तक कि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के साथ में उद्यम को प्रयोक्तव्य संविदाकारी राज्य की सरकार की सरकारी नियितों से प्रत्यक्षतः अथवा प्रत्यक्षतः पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से सहायता नहीं दी जाती है।

अनुच्छेद-6

अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति से आय उस संविदाकारी राज्य में ही करावेय हो सकेगी जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2. "अचल संपत्ति" पद की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि और व्यवहार के अनुसार की जाएगी, जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के उपसाधन के रूप में संपत्ति, हृषि और वन-संपत्ति में प्रयुक्त पशुबन्धन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार, जिन पर पूर्णप्राप्ति संबंधी सामान्य कानून के उपर्युक्त लागू होते हैं। अचल संपत्ति को भोगने का अधिकार, वनिज घंडाओं, तेल के कुओं, खाद्यान्नों तथा प्राकृतिक संसाधनों के निकालने के अन्य स्थानों की उपलब्ध अथवा उपलब्ध रखाने के एक रूपाने के कारण प्रतिफल के रूप में परिवर्तीय अथवा नियत अवायवियों के अधिकार-जलयान तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराम्पराक 1 के उपर्युक्त, अचल संपत्ति के प्रस्तावतः प्रयोग से, किराए पर देने अथवा प्रयोग के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराम्पराक 1 और 3 के उपर्युक्त किसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वाली आय और व्यावहारिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार के लाभ

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा अब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के भाष्यम से कारोबार न करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उसने अंश पर ही कर लगाया जो (क) उस स्थायी संस्थापन (छ) उस दूसरे राज्य में उसी प्रकार की वस्तुओं अथवा तिजारी माल की जो उस स्थायी संस्थापन के भाष्यम से की जाती है। अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही प्रथ्य गतिविधियों मध्यवा उसी प्रकार की गतिविधियों के कारण हुया माना जा सकता है जो उस स्थायी संस्थापन के भाष्यम से की जाती हों।

2. पैराम्पराक 3 के उपर्युक्ती के अधीनी रहने हुए, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन द्वारा कारोबार करना हो तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ की संस्थापन का ही लाभ समझा जाएगा, जिसे उसके द्वारा प्राप्त

होने की तब प्रयेक्षा की जाती जब वह उन्हीं या बैसी ही परिस्थितियों में उम्हीं या ऐसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्दम होता और उस उद्दम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र हप से कारोबार करता जिनका यह स्थायी संस्थापन है। वहस्त्राम, जहाँ स्थायी संस्थापन के कारण हुए या माने जा सकते बाले लाभों की सही रकम निश्चित नहीं की जा सकती ही अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन ही तो स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जा सकते बाले लाभों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जाए।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को, उस राज्य के कारोबार कानूनी के उपबंधों के अनुसार तथा उनमें निर्धारित सीमा के अधीन रहते हुए, कटीकार्यों के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, जोहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र। लेकिन, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्दम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्तियों से भिन्न हूप में) आदा की गयी रायलिट्यों, पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले कीस तथा इसी प्रकार की अन्य भद्रायगियों अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रधान के बावजूद उद्दम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उद्धार दिए गए घन पर व्याज के रूप में, यदि कोई रकमें आदा की गयी हों, तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटीकी की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों की हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्दम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न हूप में) स्थायी संस्थापन द्वारा रायलिट्यों, पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में कीस अथवा अन्य अधिकारों के लिए प्रधान के बावजूद उद्दम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्दम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उद्धार दिए गए घन पर व्याज के रूप में उद्दम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालयों को प्रभारित की गई हो।

4. कोई लाभ, मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन का हुए नहीं माने जाएगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्दम के लिए मान अथवा पाण्य वस्तु प्रदायी गई है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने जाने लाभों को तब तक उसी पद्धति से प्रवर्तित निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विवर कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ लाभों में आय की ये भेद शामिल हों जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में भलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपर्युक्त इस अनुच्छेद के उपर्युक्त से प्रभावित नहीं होते।

अनुच्छेद—9

विमान-परिवहन

1. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के उद्दम द्वारा विमान संचालन से प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वायुयान उस दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच पूर्णतः अथवा मुश्वरतः संचालित न किया जाना हो।

2. पैराग्राफ 1 विमान परिवहन में लगे उद्दमों द्वारा किसी भी प्रकार के पूलों में भाग लेने के संबंध में इसी प्रकार लागू होगा।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय वातावाह में वायुयान संचालन से प्रत्यक्षतः संबंधित व्ययों पर अमाज को से शायुयान संचालन से होने वाली आय माना जाएगा।

अनुच्छेद—9

स्थिरोगी उद्दम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्दम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्दम के प्रबंध, नियन्त्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्दम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्दम के प्रबंध नियन्त्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों ही मामलों में दोनों उद्दमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी गई प्रधाना लगाई जाती हैं जो ऐसी शर्तों से भिन्न हैं जो सी भवित्व उद्दमों के बीच रखी गई होती बहाँ ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की हालत में उन उद्दमों में से एक उद्दम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ, जो वह लाभ उस उद्दम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तदनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद—10

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को आदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. नथागि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी लाभांश देने वाली कम्पनी निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्थानी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर नीचे बढ़ाई गई रकम से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत यदि हितभागी स्थानी, कोई ऐसी कम्पनी है जिसके पास लाभांश आदा करने वाली कम्पनी के कम से कम प्रतिशत शेयर हों,

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम का 25 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के करगान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश आदा किए जाते हैं।

3. इन अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “लाभांशों” शब्द का अधिकार्य ऐसे शेयरों अथवा अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो अण-दावे नहीं हों, जो लाभ में शामिल हों तथा अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिन पर उसी प्रकार की करगान अध्यन्या लागू होती है जिस प्रकार उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में सागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का हितभागी स्थानी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनके लाभांश आदा करने वाली कम्पनी निवासी है, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से व्यापार करता है अथवा उन दूसरे राज्य में, स्थित एक नियन्त्रित स्थान से स्वतंत्र क्षेत्रिक सेवाएं करता है और जिस शास्त्रिना के बारे में लाभांशों के अदायगी को जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियन्त्रित स्थान से प्रभावित नहीं होगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभांश आदा प्राप्त करती है, वह वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा आदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर

नहीं भगाएगा सिवाए उस स्थिति के जब कि इस प्रकार के लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाने हैं अथवा जिस धारणाधिकार के संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी मंस्थापन अथवा किसी निषिद्ध स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो और न ही कम्पनी के अविनियत लाभों पर कम्पनी के अविनियत लाभों में सम्बद्धी कर लगाया, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अविनियत लाभों में, इस प्रकार के दूसरे राज्य में पूर्ण रूप से अथवा प्राथमिक रूप से उत्पन्न होने वाला लाभ अथवा आय शामिल नहीं न हो।

अनुच्छेद-11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह अर्जित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्थानी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए, भी—

(क) एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर से छूट वी आएगी व्यक्तों कि वह निम्ननिषिद्ध द्वारा प्राप्त किया गया हो या उनका उस पर वित्तांश स्वामित्व हो,

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक।

(ख) एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले व्याज को उस राज्य में कर से छूट हो जाएगी यदि उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का हितभागी स्वामित्व हो और वह निम्ननिषिद्ध द्वारा लिए गए अथवा समिति अर्ण अथवा उधार के बन्ध में प्राप्त किया जाता हो :

(i) जेकोस्लोबाकिया के मामले में जेकोस्लोबोरेका ऑफोडनी बैंक, जिस सीमा तक ऐसा व्याज केवल आयातों-नियातों की वित्तव्यवस्था करने के कारण होता है,

(ii) भारत के मामले में, भारतीय आयात-नियात बैंक (एपिम बैंक) जिस सीमा तक ऐसा व्याज केवल आयातों-नियातों की वित्तव्यवस्था करने के कारण होता है,

(iii) किसी संविदाकारी राज्य के विदेशी व्यापार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था करने वाला कोई संस्थान,

(iv) कोई भी अन्य व्यक्ति वशमें कि अर्ण अथवा उधार प्रभागीलिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

4. इस अनुच्छेद में व्याप्रयुक्ति "व्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के अर्ण संबंधी दातों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे अर्णादाता के लाभों में भागीकारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा अर्ण-पक्षों जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्ध-पक्षों अथवा अर्ण पक्षों के संबंध में प्रवान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय। विनियमित अर्णादाती के लिए अर्णदण्ड सम्बन्धी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोगन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्थानी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य जिसमें व्याज अर्जित हुआ हो, रियत किसी स्थायी स्थानान के भाव्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निषिद्ध स्थान से वही स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाए करता है और जिस अर्ण-दावे के बारे में व्याज अदा किया जाता है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निषिद्ध स्थान हो, जिसके संबंध में वह अर्ण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निषिद्ध स्थान द्वारा बहन किया है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निषिद्ध स्थान स्थित है।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज, उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य की राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निषिद्ध स्थान हो, जिसके संबंध में वह अर्ण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निषिद्ध स्थान द्वारा बहन किया है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निषिद्ध स्थान स्थित है।

7. जहाँ, व्याज अदा करने वाले और हितभागी स्थानी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विणेप सम्बन्ध होने के कारण, अदा की गयी व्याज की रकम, उस अर्ण-दावे को ध्यान में रखने हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की विवित में, अदा करने वाले और हितभागी स्थानी के बीच महमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध अनियम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबन्धों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायनियां और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायनियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसिन, इस प्रकार की रायनियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर भी उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पन्न हुये हों। परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायनियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्थानी होती हो तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायनियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में व्याप्रयुक्ति "रायनियों" शब्द से अभिप्रेत है किसी साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक वृत्तियों, जिसमें चलनचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा प्रसारण के लिए किलमो अथवा टेपों के प्रतिसिद्धाधिकार, कोई पेंटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान गूस कार्मिला अथवा प्रियोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अर्णवा औदांगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर अथवा औदांगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित जानकारी के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी।

4. इस अनुच्छेद में व्याप्रयुक्ति "तकनीकी सेवाओं" के लिए फीस", पद से अभिप्रेत है प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा प्रगमणादाती व्यवस्थ की सेवाओं, जिनमें तकनीकी सेवाओं की सेवाओं की अदायगी

भी शामिल है, के प्रतिक्रिया में, अदायगियों करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गई अदायगियों से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को की गई किसी भी रकम की अदायगिया।

5. ऐग्राहक 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होते यदि रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्थानी, जो जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और उम दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें गणराज्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उत्पन्न होते हैं, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से फारोबार करता है अथवा वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से खत्मन्त्र बैयकितक सेवाएं करता है और जिस प्रथकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के कारण रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस भ्रवा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हैं, । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होते ।

6. रायलिट्डियो और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुए माने जाएंगे भविष्य प्रदा करने वाला स्थायं वह राज्य कोई गजनीतिक उप-प्रधारण, कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहाँ रायलिट्डियो और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस प्रदा करने वाले अधिकतम का, आइ वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो प्रथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित स्थान हो जिम्मे संबंध में रायलिट्डियो अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस प्रदा करने का दायित्व बना हो, और इस प्रकार की रायलिट्डियो अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित स्थान द्वारा बहल की जाती हों तो इस प्रकार की रायलिट्डियो प्रथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उत्पन्न हुई समझी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित स्थान स्थित हो।

7. जहाँ, अदाकर्ता और हितभागी स्वामी प्रथम उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायलिंटियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जो इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में अदा की गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपर्युक्त केवल भ्रमित वार्णित रकम पर ही लागू होगे। ऐसी स्थिति में, अदायगियों के अतिरिक्त अंश पर, इस करार के अन्य उपर्युक्तों पर समुचित ध्यान देते हुए, प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

ग्रन्तचालन- 13

ਪੁੰਜੀਗਨ ਸਾਮ

1. एक संविदाकारी ग्रन्थ के किसी निवासी द्वारा, भनुष्ठेद 6 में उल्लिखित तथा दूसरे संविदाकारी ग्रन्थ में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त साधों पर उस दूसरे ग्रन्थ में कर लगाया जा सकेगा।

2. चल सम्पत्ति के अन्तरण से, जो एक सविदाकारी राज्य के उद्यम की उस स्थायी संस्थापना की व्यापारिक सम्पत्ति के अंग के रूप में दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित है, प्रथमा किसी सिविलिट स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से, जो एक सविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे सविदाकारी राज्य में स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, हाँने वाले लाभों पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (प्रकल्प अप्रथमा समूर्ध उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के अन्तरण से हाँने वाले लाभ भी शामिल हैं, उम्ह दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अस्तरीय यानायात में चलाये जाने वाले जलयानों अधिकारीयों द्वारा उपर्युक्त अधिकारी द्वारा प्रकार के जलयानों अधिकारीयों के परिवासन से संबंधित चल गम्भीर के अंतरण से प्राप्त लाभ पर केवल उस संविदाकारी रूप से कह काया जा सकेगा जिसका अनुरोक्ति निश्चासी हो।

4. किसी ऐसी काम्पनी के पूँजी स्टाफ के शेररों के अंतरण से होने आये लाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मंडिवा-कारी राज्य में स्थित मूल्यतः ग्रचल सम्पत्ति है, उस राज्य में कर नगाया जा सकेगा।

5. किसी कम्पनी के, जो एक मंविकाकारी राज्य की भिकाई हैं पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के प्रबन्धण से होने वाले लाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पैराप्राप्त 1,2,3,4 नथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति में भिन्न सम्पत्ति के अंतरण से होने वाली लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निबासी है।

पर्वत-चौदह- 14

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी प्रकार के दूसरे स्तरम् कार्यकलापों में निष्पादन से प्राप्त आय निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय जब ऐसी आय पर भी दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगाने योग्य होगी :

(क) यदि उसे आपने कार्यकलारों के निपादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हों, उस स्थिति में, केवल उसकी उत्ती आय पर ही उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसनी कि उस निश्चित स्थान के कारण हुई भावी जा सकती हो;

(क) यदि उस दूसरे राज्य में उसकी उपस्थिति संगत “पिछले वर्ष प्रथमा भाग वर्ष” में, जैसी भी स्थिति हो, कुल भिसाकर 90 बिनों की प्रवधिया प्रवधियों प्रथमा उससे प्रधिक की प्रवधियों की हो, तो उस स्थिति में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी भाग पर ही कर लग सकेगी जितनी कि उस दूसरे राज्य में किये गये उसके कार्यकालों से प्राप्त हुई हो।

2. “बृतिक सेवा” पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिक साहित्यिक, कलात्मक एवं भौतिक प्रयोगशाला प्रधायापन मंबंधी कार्यकलाप तथा कार्य-चिकित्सकों, शास्त्र चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, वैतनिकत्वकों और लेखकों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल है।

अनुच्छेद- 15

पराश्रीत वैष्णवितक सेषाण्

1. प्रान्तुष्ठेव 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 के उपर्यन्तों के अधीन रहते हुए, एक संविधानकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वैतन, मनवूरी तथा इसी प्रकार के अस्य पारिश्रमिक पर तब तक केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा जब तक कि नियोजन उस दूसरे संविधानकारी राज्य में नहीं किया जाता। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. परामार्फ 1 के उपबंधों के होने द्वारा भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी मिवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर के केषल प्रथमोलिखितिन राज्य में ही लग सकेगा यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत “पिछले वर्ष” अधिकार “आय वर्ष” में, जैसी भी स्थिति हो, फुल मिलाकर 183 विन से अनधिक की अवधि अधिकार अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा।

(क) पारिश्रमिक की व्यवस्थाएँ ऐसे नियोजक द्वारा अपनी की ओर से की गई हों जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चिन्त स्थापन द्वारा वह तत् नहीं किया जाता है जो नियोजन का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य के किसी उद्धम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में परिवासित किसी अल्यान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-16

निवेशकों की फीस तथा उच्चस्तर के प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निवेशक मंडल के सदस्य की हैमियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निवेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के उच्चस्तर के प्रबंधकीय पद के अधिकारी की हैमियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त बेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के हूमरे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद - 17

कामकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे कि रंगमंच, चलचित्र, रेडियो अथवा ट्रूटदर्शन कलाकारों, संगीतकारों) अथवा खिलाड़ियों द्वारा अपने इस प्रकार के वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें ये कार्यकलाप किये जाते हैं।

बाहरें कि ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों के उस राज्य के दौर का छव्वा प्रस्तर रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य की भावना उसके राजनीतिक उप-मंडल अथवा स्थानीय या गांविधिक प्राधिकरणों को नियंत्रण में है।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोगनार्थ “मार्जनिक निधि” पद का नाम एक संविदाकारी राज्य की अथवा उसके राजनीतिक उप-मंडल अथवा स्थानीय या गांविधिक प्राधिकरणों को नियंत्रण में है।

अनुच्छेद-18

मरकारी सेवा के संबंध में
पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से नियोजित पर कर केवल उस राज्य में ही लगाया जा सकेगा।

(ख) नथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर करके उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो (1) उस राज्य का राजिक है, अथवा (2) मात्र सेवा करने के प्रयोगनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बता :

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य के अथवा उसके राजनीतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा स्था-

नीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सुनित निषियों से किसी व्यक्ति को की गई किसी भी पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा यदि वह व्यक्ति उस दूसरे राज्य का निवासी नथा गरिष्ठ है।

3. अनुच्छेद 15, 16 तथा 17 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य अथवा उनके किसी राजनीतिक उप-मंडल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारबाहर के संबंध में की गई सेवाओं के भारे में प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशनों पर लग लाये जाएँगे।

अनुच्छेद - 19

और गरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के अन्यरंत के स्वेच्छों में प्राप्त की जा रही, अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न, किसी पेंशन, अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोन्लिंकित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. “पेंशन” शब्द का अर्थ उस नियतकालिक भुगतान से है जो विशेष समय में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दोगन शारीरिक चांच की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. “वार्षिकी” शब्द का अर्थ उस उल्लिखित गशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए अदायविधायिक करने के किसी वार्षिक वे अद्योत जीवनपर्याप्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा नियन्त्रित समयावधि के दोगन उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रणिधि

1. कोई व्यक्ति, जो संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल निम्नलिखित कारणों से अस्थायी रूप से :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय के छात्र के रूप में अथवा

(ख) व्यापारिक प्रणिधि के रूप में, अथवा

(ग) सरकारी धार्मिक, पूज्यार्थ, वैशानिक, माहितियाक अथवा शैक्षणिक संगठन से अध्ययन अथवा शोध कार्य के मूल प्रयोजनार्थ अनुदान, जनों अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में सैजूद रहता है, उग पर उम दूसरे राज्य में :-

(कक) उपके भरण-पोषण, शिक्षा, प्रणिधि, अध्ययन अथवा शोध कार्य के प्रयोगान्वयन विदेशों में प्राप्त रकमों पर, तथा,

(खख) अनुदान भर्ते अथवा पुरस्कार पर कर नहीं लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद स्थान अनुच्छेद 21 के प्रयोगनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस निविदाकारी राज्य का उस “पिछले वर्ष” अथवा “कैलेंडर वर्ष” में, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दोहरा करता अथवा नकास पूर्वकी “पिछले वर्ष” अथवा “कैलेंडर वर्ष” में निवासी रहा हो।

अनुच्छेद - 21

प्राधिकारी, अध्यापकों तथा शोध छात्रों का
प्राप्त अवधिग्रन्थ

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वनियालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा दूसरी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दीर्घ कारने से तकाल पूर्ण संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिषद्विक पर उस दूसरे राज्य में उसके पहुँचने की सारीक से 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होती।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होता यदि ऐसा शोध कार्य मुश्यमः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "मान्यता प्राप्त संस्था" का अर्थ ऐसी संस्था से है जिसे संवैधित संविदाकारी राज्य के गत्तम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन इसे हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की बे मद, जहाँ-कहाँ उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग गयी होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभ्रष्ट अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होते, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारबाह करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में इन निषिद्ध स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है और जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा तिथिवस्तु स्थान से प्रभावी रूप से प्रस्तुत है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी विधि हो, लागू होते।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मार्दों पर, जिनका इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों की संविदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शामिल करने रहने मिलाये हैं कि जहाँ इस करार से उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनाये जाने हैं।

2. दोनों संविदाकारी राज्य में दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(क) जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी नेमी आय प्राप्त करता है, जिस पर, इस करार के उपबंधों के अनुसार, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहाँ

प्रथमोलिलित राज्य, इस पैराग्राफ के उपर्याके (ब) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय को कर से छूट दे सकता है परन्तु उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की रांगनां करने में कर की वह बर लागू कर सकता है जो उस व्यक्ति में लागू होती यदि छूट प्राप्त आय पर हम प्रकार की छूट नहीं दी गयी होती।

(ख) दोनों ही संविदाकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाते समय, कर के उस आधार में जिस पर इस प्रकार के कर लगाये जाते हैं, आय की उन भवित्वों को शामिल कर सकेंगे जिन पर इस करार के अनुच्छेद 10, 11, 12 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे आधार पर संगणित कर की रांग में से दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा की गई कर की राशि के बराबर की कटौती देंगे। तथापि, ऐसी कटौती प्रथमोलिलित राज्य द्वारा लगाए जाने योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होती, जैसा कि कटौती बंजार करने से पहले संगणित किया गया हो जो उस आय के अनुकूल हो जिस पर हम करार के अनुच्छेद 10, 11, 12 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपर्याके (ब) के प्रयोजनार्थ, "दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किया गया कर" प्रवाली में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गयी मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय के कराधान से संबंधित कानूनों के अंतर्गत कर लगाये योग्य आय की संगणना करने में अनुमत कटौती अदा कर की गई कटौती अथवा उस कटौती अवधि अन्यथा रूप में किसी राहत के नहीं होने की विधि में देय होती।

अनुच्छेद - 24

सम-अधिकार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्त्वंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संवैधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर हो, जो उस दूसरे राज्य के निवासी राष्ट्रियों पर देसी ही परिमितियों में अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. किसी स्थायी संस्थापन पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में है, उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा; जो उस दूसरे राज्य में उसी परिस्थितियों में तथा वैसी ही शर्तों के अधीन वही कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान के अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी वाल का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारी राज्य को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के अनिवासी व्यजितों को कोई ऐसी व्यक्तिका छूट, राहत तथा कटौतीयों को ही उपलब्ध है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंतशः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रथम्या अथवा अप्रथम्या भव्यमित्र अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोलिलित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा नामसंधी कोई ऐसी चीज अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्त्वंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर हो, जो उस प्रथमोलिलित राज्य के अन्य वस्त्रों ही उद्यमों पर उन्हीं परिमितियों तथा वैसी ही शर्तों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद से वे कर अप्रिव्रत है जो इस करार के विषय है।

अनुच्छेद-25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अधिकारी दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अन्तर्गत नहीं है, तो वह इन दोनों राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपर्युक्त उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सकाम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला, उन कार्यवाही के नीटिस की प्रतिकी तरीक से तीन बर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण ऐसा कर लगाया गया हो जो इस करार के अन्तर्गत नहीं ही।

2. यदि सकाम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे करारान के परिणाम की दृष्टि से, जो इस अधिसमय के अनुरूप नहीं है, इससे संविदाकारी राज्य के सकाम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उम मामले को हल करने के प्रयत्न करेगा। जो भी करार हो गया हो, उसे संविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित किसी भी समय-सीमा के होने के बावजूद भी कार्यान्वयित किया जाएगा।

3. इस अधिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सकाम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हृत करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे करारान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकते जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैशांकों के अधिप्राय के अंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सकाम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पक्ष अवबोहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुँचने के लिए विवारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रसीत होता हो, वहाँ ऐसा आदान-प्रदान एक शायोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के सकाम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

अनुच्छेद-26

सूचना का प्रादान-प्रवान

1. संविदाकारी राज्यों के सकाम प्राधिकारी इस करार के उपबंधों को कार्यान्वयित करने के लिए अपना कर अपवर्यन अथवा करों के परिणाम को रोकने अथवा उमका पता लगाने के लिए, जो इस करार के विषय है, इस प्रकार की सूचना अथवा इस्तावेंजों का, जो आवश्यक हों, आदान-प्रदान करेंगे। उस प्रकार आदान-प्रदान की गई किमियों द्वारा सूचना अथवा वस्तावेंज को गुना समाप्त जाएगा परन्तु उन्हें ऐसे व्यक्तियों (जिसमें व्यावायिक अथवा प्रशासनिक निकाय सम्मिलित हैं) के समन प्रकट किया जा सकता है जो उन करों के निर्वाचन, वतुत, प्रबर्तन, जांच अथवा अधिप्रायन में या उनमें संबंधित किसी घोषाली से संबंधित हो, जो इस करार के विषय हैं, या ऐसे व्यक्तियों को जिनसे इस सूचना या प्रलेख का लंबंध है।

2. सूचना अथवा वस्तावेंजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अपना किन्हीं विधिएँ भारतीयों में प्रतिवेदन निलंबन पर किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सकाम आधिकारी समय-समय पर परस्पर यह तथ करेंगे कि किस-किस सूचना का या किस-किस इस्तावेंजों का नेमी आधार पर आदान-प्रदान किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैशांक 1 के उपबंधों का यह प्रवृत्त नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं :-

(क) उस संविदाकारी राज्य अथवा इससे संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा प्रभासनिक परिवाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय लगाता,

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज संलग्न करता जो उस राज्य अथवा इससे संविदाकारी राज्य के कानूनों के प्रत्यर्गत अथवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के बीचत प्राप्त नहीं हो सकते।

(ग) कोई ऐसे सूचना अथवा दस्तावेज संलग्न करना जिससे कोई व्यापारिक, आबादायिक, आर्थोगिक, वाणिज्यिक अथवा बुनिक भैर लूल जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना जिसको प्रकट करता नार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

अनुच्छेद-27

राजनयिक तथा कौमुली अधिकारी

इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, प्रत्यर्गत्यें विधि के नामान्य विभागों के प्रत्यर्गत्यें विशेष करारों के उपबंधों के प्रत्यर्गत्यें राजनयिक अथवा कौमुली अधिकारियों के विर्त्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-28

प्रबंधन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इससे संविदाकारी राज्य को इस करार को प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके कानून के प्रधान प्रतिनिधित्व कार्यविधियों के पूरा हो जाने के बारे में प्रधिष्ठृतित करेगा। यह करार, इन अधिष्ठृतनाओं में से बाद वाले अधिष्ठृतना की तारीख को लागू होगा और उसके बाद :

(क) भारत में, अप्रैल, 1985 के प्रथम दिन अथवा उसके बाद से किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में;

(ख) चैकोस्लोवाकिया में, जनवरी, 1985 के प्रथम दिन अथवा उसके बाद से किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में, लागू होगा।

अनुच्छेद-29

समाप्ति

यह करार अनिवार्यत समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व राजनयिक नायमों से, इससे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का विद्वित नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया जाना है उसके अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाले आय के सम्बन्ध में;

(ख) चैकोस्लोवाकिया में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन वो अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में, निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके नायम में, इसके निए विधिवत् प्राधिकृत प्रधोस्ताश्रियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिनों में वर्ष एक-हजार तो सौ छाती के जनवरी मास के 27 वें दिन अप्रैल भाषा में दो प्रतियों में सम्बन्ध हुआ।

(विधवनाय प्रताप तिहू)

विध मंत्री

भारत सरकार की ओर से

(हंग जारोमीर जाफ़)

वित्त मंत्री

चैकोस्लोवाकिया सभाजनायी गणराज्य की सरकार की ओर से

The Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1 PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) In the case of India :

- (1) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (2) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1961 (7 of 1961);
- (hereafter referred to as "Indian tax")

(b) In the case of Czechoslovakia :

- (1) the taxes on profits;
 - (2) the wages tax;
 - (3) the tax on income from literary and artistic activities;
 - (4) the agricultural tax;
 - (5) the tax on population income;
 - (6) the house tax;
- (hereafter referred to as "Czechoslovak tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective laws governing the taxes which are the subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments and regulations.

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law; U. N. Convention on the Law of the Sea;

- (b) the term "Czechoslovakia" means the Czechoslovak Socialist Republic;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Czechoslovakia, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Czechoslovak tax, as the context requires;
- (e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws of the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Czechoslovakia, the Minister of Finance of the Czechoslovak Socialist Republic or his duly authorised representative.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that Contracting State in accordance with the taxation laws of that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules : —

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations and closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting

State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop or a warehouse;
- (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery or equipment.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by an enterprise of the other Contracting State;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise. However, this provision shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purpose or purposes other than the purposes herein specified.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the firstmentioned Contracting State if :

- (a) he has and habitually exercises in that Contracting State, an authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State exclusively or almost exclusively, for the enterprise itself, or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

7. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on business which consists of providing the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of

the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed only in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitation of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of these Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of aircraft by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State unless the aircraft is operated wholly or mainly between places within that other Contracting State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purpose of paragraph 1, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this article means income from shares or other rights, not being debt-claims participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid

is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 14 as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the Company undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,—

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a political sub division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

(i) in the case of Czechoslovakia, the Ceskoslovenska obchodni banka, to the extent it is attributable to financing of exports and imports only;

(ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;

(iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;

(iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term 'interest' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claims in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of such Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property,

referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprises) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities ; in that case, only so much of the income as is attributable to the fixed base may be in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the relevant "previous year" or "year of income" as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "Year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES & REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as much may be taxed only in the Contracting State in which these activities are exercised:

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public

entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term "public funds" means the funds of a Contracting State or its political sub-divisions, or local or statutory authorities.

Article 18

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State ; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof.

Article 19

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. An individual who is a resident of one of the Contracting State and is temporarily present in the other Contracting State solely, --

- (a) as a student at a recognised university, college or school in that other Contracting State, or
- (b) as a business apprentice, or
- (c) as the recipient of a grant, allowances, or award for the primary purpose of study or research from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation,

shall not be subjected to tax in that other Contracting State—

- (aa) on the remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, training, study or research, and
- (bb) the grant, allowance or award.

2. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or calendar year, as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" of calendar year.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, collage, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the State, carries on business in the other Contracting recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In both the Contracting States, double taxation will be avoided in the following manner :

(a) Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

(b) Either of the Contracting States when imposing taxes on its residents may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may also be taxed in the other State but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in the other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of tax leviable by the first-mentioned State, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, and 12 of this Agreement may be taxed in the other State.

3. For the purposes of sub-paragraph (b) of paragraph 2 the term "tax paid in the other Contracting State" shall be deemed to include any amount which would have been payable as tax but for any relief by way of the deduction allowed in computing the taxable income or an

exemption or a reduction of tax or otherwise under the laws relating to taxation of income in force in that other Contracting State.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which resident nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not residents in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding

any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinion, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or any frauds connected therewith, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April, 1985;
- (b) in Czechoslovakia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January, 1985.

Article 29

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Czechoslovakia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January one thousand nine hundred and eighty six in the English language.

(Vishwanath Pratap Singh)
Finance Minister
For the Government of India

(Ing. Jaromir Zak)
Finance Minister
For the Government of the
Czechoslovak Socialist Republic.

PROTOCOL.

At the time of signing the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on income, this day concluded between the Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic, the undersigned Plenipotentiaries have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

I. ARTICLE 5 (PERMANENT ESTABLISHMENT).

(i) The term "assembly project" as used in clause (g) of paragraph 2 includes installation of equipment.

(ii) The provisions of clauses (a) and (b) of paragraph 3 shall apply, mutatis mutandis, to a case where the use of facilities or maintenance of stock of goods or merchandise is, in addition to storage or display, for the purpose of delivery of spare parts, and component by way of replacement, during the period of the respective contract, from stock of goods stored in the Contracting State.

II. ARTICLE 8 (AIR TRANSPORT)

Notwithstanding anything contained in Article 28, the provisions of Article 8 relating to Air Transport shall be applicable from 1st January, 1981 and the tax paid, if any, will be refunded on application being made within twelve months of the entry into force of the Agreement.

(Vishwanath Pratap Singh)
Finance Minister.
For the Government of India

(Ing. Jaromír Zák)
Finance Minister
For the Government of the
Czechoslovak Socialist Republic.

No. PRA/204/2/86.Com

14th April, 1986

The Embassy of India presents its compliments to the Federal Ministry of Foreign Affairs, Government of the Czechoslovak Socialist Republic and with reference to Article 28 of the Agreement between the Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on income, signed at New Delhi on the 27th January, 1986, has the honour to state that the Government of India have complied with the requirements necessary for bringing into force of the Agreement.

2. Accordingly, the Embassy has the honour further to state that the aforesaid Agreement will enter into force with a similar note confirming that the Government of the Czechoslovak Socialist Republic have also complied with the requirements of Article 28 of the said Agreement.

3. The Embassy of India avails itself of the opportunity to renew to the Federal Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Federal Ministry of Foreign Affairs,
of the Czechoslovak Socialist Republic,
Prague.

Seal
Embassy of India
Prague.

No. 1012/87.

The Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic in India presents its compliments to the Ministry of External Affairs, Government of India, and has the honour to notify that the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed in New Delhi on 27th January 1986, has been, as required in Article 28 of the said Agreement, duly ratified in accordance with Czechoslovak legal regulations.

The Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of External Affairs the assurances of its highest consideration.

New Delhi, March 13, 1987.
Seal

Embassy of the Czechoslovak
Socialist Republic

The Ministry of External Affairs,
Government of India,
New Delhi.

[No. 7311 (F. No. 11/22/66-F.T.D.)]
V. U. ERADI, Jt. Secy.